



भारतीय विदेश नीति और चीन-पाक गठजोड़ एक चुनौती

मोहित कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान

डॉ. चुनाराम सुथार

सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, मगरा पूंजला, जोधपुर

ABSTRACT:

आजादी के बाद से ही भारतीय विदेश नीति के समक्ष कई चुनौतियाँ रही हैं। भारत को आजादी के साथ विभाजन की विभीषिका भी झेलनी पड़ी थी। विभाजन के बाद भी पाकिस्तान के शासकों ने भारत के साथ सहयोग की बजाय संघर्ष की नीति अपनायी हुई है। पाकिस्तान सदैव ही कश्मीर मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास करके भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता आया है। भारत से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में जीत न पाने के कारण ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 'जेहाद' के नाम पर आतंकवाद को अपनी राज्य नीति का अंग बना रखा है। भारत विरोधी नीति के तहत ही पाकिस्तान पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का पिछलग्गू बना रहा और वर्तमान में चीन का पिछलग्गू बना हुआ है। चीन भी अपनी विस्तारवादी नीति और वैश्विक वर्चस्व की महत्वाकांक्षा में भारत को अपना प्रतिरोधी मानता है। चीन व पाकिस्तान के साथ भारत के सीमा-विवाद भी हैं। दोनों देशों ने भारत विरोधी अपने सांझा हितों के लिए एक गठजोड़ बना रखा है इसके अलावा चीन द्वारा संचालित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना (सीपैक) पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरती है जो कि भारत की सम्प्रभुता के लिए चुनौती है। सीपैक परियोजना चीन के काश्गर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बन्दरगाह तक जोड़ती है तथा ग्वादर बन्दरगाह तक आसान पहुँच बनाती है। व्यापारिक व सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस ग्वादर बन्दरगाह को विकसित कर चीन हिन्द महासागर में अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करना चाहता है। यह चीन की भारत को सामुद्रिक रूप से घेरने की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' (मोतियों की माला) का ही अंग है। जहाँ पाकिस्तान चीन के साथ गठजोड़ को भारत के खिलाफ अपने लिए सुरक्षा कवच मानता है वहीं चीन भी भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को सीमित करने के लिए पाकिस्तान के साथ सामरिक सहयोग करता आया है। चीन जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की कश्मीर नीति का समर्थन करता है वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद के विषय पर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का बचाव करता आया है। भारतीय विदेश नीति के समक्ष चीन-पाक गठजोड़ एक चुनौती साबित हो रहा है।

KEYWORDS:

विदेश नीति, चीन-पाक गठजोड़, आतंकवाद, सीपैक, चुनौती।

परिचय

15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजाद हुआ था परन्तु भारत को आजादी के साथ पाकिस्तान के रूप में विभाजन की विभीषिका भी झेलनी पड़ी थी। साम्राज्यिक और धार्मिक उन्माद की जिस भावना के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ था उसने भारत और पाकिस्तान के बीच विरोध और तनाव की एक ऐसी सीमा रेखा खींच दी थी जिसने आज तक दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों को स्थिर नहीं बनने दिया। विभाजन के बाद भी पाकिस्तान के शासकों ने भारत के साथ सहयोग की बजाय संघर्ष की नीति अपनायी हुई है। भारत विरोधी नीति के कारण ही पाकिस्तान ने भारत के साथ विकास की सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की बजाय विरोध की नकारात्मक प्रतिस्पर्धा को ही अपनी विदेश नीति का अहम अंग बनाया। इसी प्रकार चीन भी भारत के साथ सीमा सम्बन्धी विवादों को आपसी वार्तालाप की बजाय अपनी सैन्य शक्ति के जरिए सुलझाने का प्रयास करता रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति और वैश्विक वर्चस्व की महत्वाकांक्षा में भारत को अपना प्रतिरोधी मानता है। अपने भू-राजनीतिक हितों के परिपक्व में चीन के द्वारा पाकिस्तान को भारत विरोधी गतिविधियों में सहायता दी जाती रही है। एक तरफ चीन के लिए पाकिस्तान मध्य-पूर्व के देशों और हिन्द महासागर से लेकर फारस व भूमध्य सागर तक सीधी पहुँच बनाने का माध्यम है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए चीन आर्थिक व सैन्य सुविधा प्रदान करने वाला प्रमुख मित्र देश है। अपने इन्हीं हितों की पूर्ति के लिए दोनों देश 'सदाबहार मित्रता' वाले देश बने हुए हैं।¹

चीन-पाकिस्तान गठजोड़

चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं तथा दोनों ही देशों के साथ भारत लम्बी सीमा सांझा करता है। भारत, पाकिस्तान के साथ लगभग 3323 किलोमीटर सीमा रेखा सांझा करता है जो 'रेडक्लिफ लाइन' नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार भारत व चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लम्बी सीमा रेखा है जो 'मैकमोहन रेखा' के नाम से जानी जाती है। वर्ष 1914 में ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत यह सीमा रेखा निर्धारित की गई थी परन्तु चीन इस सीमा रेखा को ब्रिटीश साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में देखता है तथा इसे स्वीकार नहीं करता। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक तीन सेक्टरों में बंटी इस लाइन ऑफ कण्ट्रोल (एल.ए.सी.) पर चीन द्वारा भारतीय सीमा क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जाता रहा है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो जाता है। स्पष्ट है कि भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा-विवाद हैं परन्तु पाकिस्तान के साथ भारत की कड़वाहट के बीच दोनों देशों के विभाजन में ही निहित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की पृष्ठभूमि ने ही दोनों देशों के बीच जिन तनावपूर्ण सम्बन्धों की आधारशिला रखी थी वो आज भी विद्यमान हैं। अलग राष्ट्र बनने के बावजूद भी पाकिस्तान की विदेश नीति सदैव भारत विरोधी दुष्प्रचार पर ही आधारित है।²

द्वितीय युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चले शीतयुद्ध काल में पाकिस्तान, 1954-55 में अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों यथा दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन (सैण्टो) और मध्य-पूर्व संधि संगठन (सीटो) में शामिल हुआ था जबकि भारत ने अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति के आधार पर इन महाशक्तियों की गुटबाजी से दूर रहते हुए 'गुटनिरपेक्षता की नीति' का अनुसरण किया था। एशिया में सोवियत संघ के साम्यवादी विचारधारा के प्रचार-प्रसार को रोकने और अपने भू-राजनीतिक हितों की पूर्ति करने के लिए सं.रा.अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रचुर मात्रा में वित्तीय सहायता एवं सैन्य सामग्री उपलब्ध करवायी थी। सं.रा. अमेरिका जैसी महाशक्ति के प्रश्रय से ही पाकिस्तान ने कभी भी भारत के साथ आपसी विवादों को वार्तालाप के माध्यम से सुलझाने की बजाय सैन्य शक्ति के प्रयोग से सुलझाने का प्रयास किया। विभाजन के कुछ माह बाद ही पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को भारत की कश्मीर रियासत पर कब्जे की नीयत से हमला कर दिया था तथा उसके एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था जो 'गुटनिरपेक्षता की नीति' (पी.ओ.के.) के नाम से जाना जाता है।³ तभी से पाकिस्तान सदैव ही कश्मीर मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास करके भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता आया है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत पर 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध थोप चुका है। भारत से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में जीत न पाने के कारण ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 'जेहाद' के नाम पर आतंकवाद को अपनी राज्यनीति का अंग बना रखा है। अपनी भारत विरोधी नीति के तहत पाकिस्तान पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का पिछलग्गू बना रहा और वर्तमान में चीन का पिछलग्गू बना हुआ है। आजादी के पहले दशक तक तो भारत और चीन क सम्बन्ध अच्छे बने रहे थे तथा अप्रैल 1954 में दोनों देशों के बीच 'पंचशील' के सिद्धान्तों पर सहमति भी बनी थी परन्तु चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति और वर्ष 1959 में भारत द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को राजनीति शरण देने की वजह से 20 अक्टूबर 1962 में भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया था तथा भारत के लद्दाख क्षेत्र का लगभग 38000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया जो अब अक्साइचिन कहलाता है।⁴ भारत के 1962 के युद्ध में चीन से हारने के बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने के लिए 1963 में चीन के साथ 'चीन-पाकिस्तान भूमि सीमा समझौते' के तहत पाक अधिकृत कश्मीर की लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन को भेंट कर दी थी।⁵ इसके बाद से ही दोनों देश अपने भारत विरोधी सांझा हितों के लिए गठजोड़ के रूप में क्रियाशील हैं।

चीन-पाकिस्तान गठजोड़ की चुनौतियाँ

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों के बावजूद भारत पाकिस्तान के साथ हमेशा अच्छे सम्बन्धों की पहल करता आया है परन्तु हर बार पाकिस्तान की तरफ से विश्वासघात किया जाता रहा है। 20-21 फरवरी 1999 को तात्कालिक भारतीय

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ मधुर सम्बन्धों के लिए न केवल दोनों देशों के बीच 'दिल्ली लाहौर बस' की शुरुआत की थी बल्कि स्वयं बस द्वारा लाहौर गये थे परन्तु जहाँ एक तरफ वाजपेयी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ 'लाहौर घोषणा' पत्र के तहत अच्छे सम्बन्धों की संधि कर रहे थे वहीं पाकिस्तान सेना भारत के द्रास-कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ कर रही थी। अपने द्रास-कारगिल क्षेत्र को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ही भारत ने पाक के साथ 1999 का 'कारगिल युद्ध' लड़ा था।⁷ वहीं चीन ने हमेशा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है इतना ही नहीं पाकिस्तान के परमाणु एवं मिसाइल विकास कार्यक्रम के संवर्धन के पीछे चीन द्वारा ही गुप्तचर तरीके से परमाणु तकनीक उपलब्ध करवायी जाती रही थी। भारत सदैव ही अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाता रहा था। भारत द्वारा 11 व 13 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण 'पोकरण द्वितीय' के मात्र कुछ दिनों के अन्तराल में ही पाकिस्तान के द्वारा 28 व 30 मई 1998 को परमाणु परीक्षणों का किए जाना भारत की इस शंका को पुष्ट करता था।⁸

इसके अलावा चीन द्वारा संचालित **चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट (सीपैक)** भारतीय सम्प्रभुता के लिए चुनौती साबित हो रहा है। चीन द्वारा संचालित सीपैक परियोजना चीन के झिनजियांग प्रांत के काश्गर को पाकिस्तान के ग्वादर बन्दरगाह तक जोड़ने वाली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके तहत परिवहन, ऊर्जा, गैसपाइप लाइन और विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण सम्बन्धी आधारभूत कार्य शामिल हैं। लगभग 1153 किलोमीटर लम्बी यह परियोजना चीन को सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण पाकिस्तान के ग्वादर बन्दरगाह तक जोड़ती है। सीपैक परियोजना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा वर्ष 2013 में घोषित महत्वाकांक्षी परियोजना 'वन बेल्ट वन रोड' (आबेर) का ही हिस्सा है। पाकिस्तान इस परियोजना का प्रमुख भागीदार देश है।⁹ भारत के लिए सीपैक परियोजना चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि सीपैक परियोजना का काफी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरता है जो कि भारत का ही भाग है। भारत लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहा है।

इसके अलावा पाकिस्तान के ग्वादर बन्दरगाह को भी चीन के द्वारा ही विकसित किया जा रहा है। चीन जहाँ सीपैक परियोजना के माध्यम से ग्वादर बन्दरगाह तक आसान व सीधी पहुँच बना लेगा वहीं चीन, पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में सीपैक परियोजना में कार्यरत अपने कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु अपनी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा ग्वादर बन्दरगाह में व्यापारिक गतिविधियों के नाम पर चीन हिन्द महासागर में अपनी सामरिक स्थिति सुदृढ़ करना चाहता है। चीन की सीपैक परियोजना से उसकी ग्वादर बन्दरगाह तक पहुँच आसान हो जायेगी तथा ग्वादर बन्दरगाह के माध्यम से वह हिन्द महासागर में सैन्य दखल करके सामरिक बढ़त लेने का प्रयास करेगा। हिन्द महासागर में चीन की उपस्थिति भारत की सामुद्रिक सीमा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। चीन ग्वादर बन्दरगाह पर अपनी पकड़ के द्वारा अमेरिका की हिन्द महासागर की उपस्थिति का भी प्रतिरोध करना चाहता है।¹⁰

भारत को सामुद्रिक रूप से घेरने की चीन अपनी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' (मोतियों की माला) योजना के तहत भी भारत के समक्ष चुनौती पेश कर रहा है। भारत की सामुद्रिक घेराबन्दी के तहत ही चीन ने बांग्लादेश के चिटगॉंग बन्दरगाह, म्यांमार के क्याक्पू बन्दरगाह, श्रीलंका के हबनटोटा बन्दरगाह और मालदीव के फेयधूफिनोहु बन्दरगाह को अपना ठिकाना बना चुका है और पाकिस्तान का ग्वादर बन्दरगाह भारत को सामुद्रिक रूप से घेरने की उसकी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' नीति का अंतिम छोर है। इस प्रकार जहाँ चीन-पाकिस्तान का गठजोड़ सीपैक परियोजना के माध्यम से भारत को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से दबाव में डाल रहा है वहीं ग्वादर बन्दरगाह के माध्यम से भारत की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ा कर रहा है।¹¹

चीन व पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रश्रय की नीति

चीन जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की कश्मीर नीति का समर्थन करता है वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर बचाव करता आया है। चीन ने भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र संघ की वैश्विक आतंकी सूची में डालने के प्रस्तावों में कई बार अड़गा लगाया है। मसूद अजहर की भारत में घटित अधिकांश आतंकी घटनाओं में प्रमुख भूमिका रही है। भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए मसूद अजहर ने वर्ष 2000 में पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद संगठन की स्थापना की थी।¹² पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इण्टर सर्विसेज इण्टेलिजेन्स (आई.एस.आई.) पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को भारत विरोधी गतिविधियों में प्रशिक्षण से लेकर हथियार तक मुहैया करवाती है। विदित हो कि मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए ही 24 दिसम्बर 1999 को भारतीय इण्डियन एयरलाइन्स के विमान आई.सी.-814 का अपहरण कर कांधार (अफगानीस्तान) ले जाया गया था।¹³ 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में बी.एस.एफ. के काफिले पर हुए आतंकी (पुलवामा हमला) हमले के बाद भारत ने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र संघ की वैश्विक आतंकी सूची में डालने का प्रस्ताव पेश किया था जिसका समर्थन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 सदस्यों ने किया था परन्तु चीन ने अपनी निषेधाधिकार शक्ति (वीटो पावर) के प्रयोग से इस प्रस्ताव को खारिज करवा दिया था।¹⁴ चीन ने

इससे पहले भी वर्ष 2009, 2016 और 2017 में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी सूची में डालने के प्रस्तावों को खारिज करवा दिया था। इसी तरह चीन ने सितम्बर 2022 में न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सम्मेलन में 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई में हुए आतंकी हमले के मुख्य आरोपी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। इस बार भी सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन में थे। विदित हो कि साजिद मीर चौथा ऐसा पाकिस्तानी आतंकवादी है जिसका बचाव चीन ने किया है। इससे पहले भी चीन ने पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल रउफ व मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्तावों का विरोध किया था।¹⁵

चीन की पाकिस्तानी आतंकवाद को प्रश्रय देने की इसी नीति पर प्रहार करते हुए वर्तमान भारतीय विदेशमंत्री एस.जयशंकर ने सितम्बर 2022 में न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 77 वें सत्र को संबोधित करते हुए चीन व पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा था कि "एक तरफ पड़ोस से आतंकवाद को भारत के खिलाफ प्रायोजित किया जा रहा है तो दूसरा पड़ोसी देश उसे बचाने और आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने में अड़गा लगाता है।" भारतीय विदेशमंत्री एस.जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा से ऐसे देशों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की भी मांग की थी।¹⁶

आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देने की नीति के कारण ही पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरा माना जाता है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना है क्योंकि पाकिस्तान के अस्थिर राजनीतिक हालातों और वहाँ पर कट्टरपंथी विचारधारा व आतंकवादी संगठनों पर नियन्त्रण न होने के कारण पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का आतंकवादियों के हाथों में जाने का खतरा सदैव बना रहता है। विदित हो कि पाकिस्तान के पास लगभग 165 के करीब परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल नाम की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 45 से अधिक आतंकी संगठन सक्रिय हैं। अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-जिहाद और जैश-ए-मोहम्मद जैसे 12 से अधिक आतंकी संगठनों को गतिविधियाँ विदेशों तक फैली हुई हैं।¹⁷ पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के फलने-फूलने के कारण ही आतंकवाद के वित्तपोषण पर निगरानी तथा मनीलान्ड्रिंग पर नियन्त्रण करने वाली पेरिस (फ्रांस) स्थित वैश्विक संस्था फाइनेशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफ.ए.टी.एफ.) ने फरवरी 2018 से ही पाकिस्तान को आतंकी संगठनों की फंडिंग पर रोक लगाने में नाकाम रहने के कारण विश्व की प्रमुख आर्थिक संस्थाओं को पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने पर रोक लगा रखी थी तथा पाकिस्तान को 'ग्रे' लिस्ट में था। पाकिस्तान के इससे भी निम्नतम 'ब्लैक लिस्ट' जाने की भी सम्भावना थी परन्तु चीन के द्वारा लगातार बचाव करते रहने के कारण वह 'ग्रे लिस्ट' में ही रहा। हालांकि 21 अक्टूबर 2022 को पेरिस में आयोजित एफ.ए.टी.एफ. की बैठक में पाकिस्तान को चार साल बाद 'ग्रे' लिस्ट से बाहर कर दिया है।¹⁸ जिस पर भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज करवायी है क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी व आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है।

निष्कर्ष

पाकिस्तान का भारत से विभाजन जिस साम्प्रदायिक भावना व धार्मिक उन्माद की पृष्ठभूमि में हुआ था वह बदस्तूर आज भी जारी है। भारत के साथ नकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण पाकिस्तान पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और अब चीन का पिछलग्गू है। चीन भी अपनी वैश्विक वर्चस्व की महत्वाकांक्षा और विश्व में भारत की बढ़ती लोकप्रियता के कारण भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है। दक्षिण एशिया में भारत को घेरने की नीति के तहत तथा भारत विरोधी सांझा हितों के कारण चीन-पाकिस्तान ने गठजोड़ बना कर भारत की विदेश नीति के समक्ष सामरिक चुनौतियाँ खड़ी की हुई हैं। निःसन्देह भारत को चीन-पाकिस्तान गठजोड़ से निपटने के लिए सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के अलावा अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया आदि देशों से मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा।

REFERENCES

- स्माल, एण्ड्रयू, द चाइना पाकिस्तान एक्सिस : एशियाज, न्यू जियोपॉलिटिक्स, पेंगुइन रेण्डम हाउस इण्डिया प्रा.लि, गुडगांव, 2020, पृष्ठ-1
- प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2013, पृष्ठ-285
- खन्ना, वी.एन., भारत और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, साहित्य भवन प्रा.लि., आगरा, 2005, पृष्ठ-197

4. सिंह, रहीस, वैश्विक सम्बन्ध, डार्लिंग किंडरस्ले (इण्डिया) प्रा.लि., नोयडा, 2013, पृष्ठ- 158-159

5. राघवन, के.एन., डिवाइडिंग लॉइन्स : कॉनट्रर्स ऑफ इण्डिया-चाइना डिस्कार्ड ,लिडस्टार्ट पब्लिशिंग प्रा.लि., मुम्बई, 2018, पृष्ठ- 231-239

6. कुमार, अशोक, विपुल अनेकांत, भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियाँ, मैग्राहिल एजुकेशन (इण्डिया) प्रा.लि., चैन्नई, 2020, पृष्ठ-10.3

7. यादव, आर.एस., भारत की विदेश नीति, डार्लिंग किंडरस्ले (इण्डिया) प्रा.लि., नोयडा, 2013 पृष्ठ- 155-158

8. दीक्षित, जे.एन., भारत-पाक सम्बन्ध (युद्ध और शांति में), प्रभात पेपर बैक्स प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृष्ठ- 374-376

9. दैनिक भास्कर, 1मई, 2022, पृष्ठ-13

10. वर्ल्ड फोकस, अंक-71, फरवरी 2018, पृष्ठ- 72-73

11. वर्ल्ड फोकस, अंक-57, दिसम्बर 2016, पृष्ठ-39

12. सिंह, आशीष विक्रम, भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में अमेरिकी नीति, फर्स्ट प्रिन्ट पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2018, पृष्ठ-85

13. दत्त, वी.पी., बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति, भाग-2, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2015, पृष्ठ-565

14. दैनिक भास्कर, 13 व 14 मार्च 2019, पृष्ठ- 4 व 1

15. दैनिक भास्कर, 18 सितम्बर 2022, पृष्ठ-1

16. दैनिक भास्कर, 26 सितम्बर 2022, पृष्ठ-5

17. दैनिक भास्कर, 18 अक्टूबर 2022, पृष्ठ-9

18. दैनिक भास्कर, 22 अक्टूबर 2022, पृष्ठ-1